



नांदेड-वाघाळा मनपा चुनाव 2026 : AIMIM की एंट्री, दल-बदल और आरोप-प्रत्यारोप से गरमाई राजनीति

संपादकीय... |

नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका चुनाव 2026 से पहले शहर की राजनीति जिस तीव्रता और उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह चुनाव अब सामान्य स्थानीय निकाय चुनाव नहीं रहा। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और पूर्व नगरसेवकों का AIMIM में प्रवेश, बड़ी संख्या में पार्षदों का भाजपा में जाना और इसके बाद शुरू हुए खुले आरोप-प्रत्यारोप ने नांदेड की राजनीति को निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है।

यह स्थिति केवल दल-बदल तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक विश्वास, नेतृत्व की विश्वसनीयता और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे गहरे सवालों को भी सामने ला रही है।

AIMIM की एंट्री और कांग्रेस के सामने खड़ा संकट

नांदेड को लंबे समय तक कांग्रेस का मजबूत राजनीतिक आधार माना जाता रहा है, विशेषकर मुस्लिम-बहुल प्रभागों में। लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इस पारंपरिक समीकरण को झकझोर कर रख दिया है। पूर्व महापौर सहित कई प्रभावशाली नेताओं और नगरसेवकों का AIMIM में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के भीतर नेतृत्व संकट, संगठनात्मक कमजोरी और अल्पसंख्यक नेतृत्व की उपेक्षा जैसे सवाल खुलकर सामने आए हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि AIMIM की सक्रियता कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने की रणनीति का हिस्सा है और इससे भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की आशंका है।

दल-बदल की राजनीति और भाजपा की बढ़त

कांग्रेस के लिए चुनौती यहीं समाप्त नहीं होती। बड़ी संख्या में पूर्व पार्षदों और वरिष्ठ नेताओं का भाजपा में जाना इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर असंतोष लंबे समय से पनप रहा था। पूर्व महापौर, उपमहापौर और अनुभवी नगरसेवकों के भाजपा में शामिल होने से स्थानीय राजनीति का संतुलन बदला है।

भाजपा इसे कांग्रेस की नीतिगत विफलता और नेतृत्वहीनता का परिणाम बता रही है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस से नेताओं का पलायन जनाधार के खिसकने का संकेत है और जनता अब वैकल्पिक नेतृत्व की ओर देख रही है।

आरोप-प्रत्यारोप का दौर राजनीतिक घटनाओं के साथ-साथ आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं ने AIMIM पर चुनाव को साम्प्रदायिक दिशा में ले जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस प्रकार की राजनीति से नांदेड की सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंच सकता है।

इसके जवाब में AIMIM नेताओं ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी किसी दल की 'बी-टीम' नहीं है। AIMIM का तर्क है कि वह उन नेताओं और वर्गों को राजनीतिक मंच दे रही है जिन्हें वर्षों तक नजरअंदाज किया गया। AIMIM इसे राजनीतिक अवसरवाद नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व की लड़ाई बताती है।

भाजपा ने भी स्पष्ट किया है कि उसका AIMIM से कोई संबंध नहीं है और कांग्रेस अपनी अंदरूनी कमजोरियों को छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ रही है।

असली मुद्दों से भटकती बहस इस पूरे राजनीतिक शोरगुल में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि नांदेड के बुनियादी नागरिक मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। पानी की समस्या, जर्जर सड़कें, जलनिकासी, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार जैसे सवाल मतदाताओं के लिए प्राथमिक हैं, लेकिन राजनीतिक दल इन मुद्दों पर ठोस चर्चा करने के बजाय एक-दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं।

कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय यह पूरा घटनाक्रम कांग्रेस के लिए चेतावनी से कम नहीं है। एक ओर भाजपा की आक्रामक रणनीति, दूसरी ओर AIMIM का उभार और भीतर से कमजोर संगठन — इन तीनों के बीच कांग्रेस की राह कठिन होती जा रही है। यदि पार्टी समय रहते नेतृत्व, संगठन और कार्यकर्ताओं के विश्वास को मजबूत नहीं करती, तो मनपा चुनाव में उसे गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है।

हालांकि यह भी सच है कि कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कई क्षेत्रों में आज भी पार्टी को समर्थन प्राप्त है, लेकिन उसे नए सिरे से रणनीति और नेतृत्व पर काम करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका चुनाव 2026 अब केवल सीटों का गणित नहीं रहा। यह चुनाव राजनीतिक नैतिकता, प्रतिनिधित्व और जनविश्वास की कसौटी बन चुका है। AIMIM की एंट्री, बड़े पैमाने पर दल-बदल और तीखे आरोप-प्रत्यारोप ने चुनावी तापमान जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय नांदेड की जनता के हाथ में है।

यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मतदाता भावनात्मक और आरोप-प्रधान राजनीति से ऊपर उठकर विकास, स्थिरता और सुशासन को प्राथमिकता देते हैं या फिर यह चुनाव नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की दिशा में आगे बढ़ता है।

WORLD NEWS | भारत ने 'प्राणदान' देकर अफगानिस्तान से निभाई दोस्ती

भारत ने 'प्राणदान' देकर अफगानिस्तान से निभाई दोस्ती, पाकिस्तानी ब्लैकमेल खत्म, तालिबानी कर रहे तारीफ

NEWS AGENCY

काबुल: पाकिस्तान के हवाई हमले और दवाओं को लेकर ब्लैकमेल किए जाने के बीच भारत और अफगानिस्तान में दोस्ती अब और मजबूत होती जा रही है। भारत ने तालिबान सरकार से किया गया अपना वादा पूरा किया है और अफगानिस्तान को अत्याधुनिक एंबुलेंस की एक खेप सौंप दी है। इससे पहले तालिबानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की दिल्ली यात्रा के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह वादा किया था। जयशंकर ने उस समय कहा था कि भारत की ओर से 20 एंबुलेंस की खेप सद्भावना गिफ्ट है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत अफगानिस्तान के हॉस्पिटल्स के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन मुहैया कराएगा। साथ ही बच्चों की वैक्सिन और कैंसर की दवाएं भी देगा।

रिपोर्ट के मुताबिक एंबुलेंस देना भारत और अफगानिस्तान के बीच हेल्थकेयर कोऑपरेशन का हिस्सा है। भारत काबुल में इंदिरा गांधी के नाम पर बने बच्चों के अस्पताल को गरम रखने का सिस्टम बदलेगा और यहां के इलाज के



आधुनिक सिस्टम भी लगाएगा। इसके अलावा भारत काबुल के बगरामी जिले में एक 30 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहा है। इसके अलावा पाकटीका, खोशत और पाकटिआ प्रांतों में महिलाओं के लिए क्लिनिक बनाए जाएंगे। भारत अफगान लोगों को कृत्रिम अंग दान कर रही है जिसकी अफगान सरकार ने जमकर तारीफ की है। पिछले महीने ही अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री भारत के दौरे पर आए थे।

तालिबानी कर रहे भारत की तारीफ

अफगान हेल्थ मिनिस्टर ने भारतीय समकक्ष के साथ दवाओं की लंबे समय तक आपूर्ति, क्षमता निर्माण और आधारभूत ढांचे में सहयोग पर बात की थी। इस दौरान भारत ने कैंसर की दवाओं और सीटी स्कैनर सौंपकर अपने इरादों को साफ कर दिया था। भारत के एंबुलेंस देने की सोशल मीडिया में तालिबानी जमकर तारीफ कर रहे हैं। अफगान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि लंबे समय से अफगान जनता इलाज के लिए भारत आती रही है। मेडिकल वीजा एक बेहद अहम मानवीय चैनल है। अफगान सरकार अब अत्याधुनिक अस्पताल बनाने पर काम कर रही है।

पाकिस्तान का ब्लैकमेल होगा खत्म

अफगानिस्तान अभी तक करीब 60 फीसदी दवाएं पाकिस्तान से आयात करता था लेकिन दोनों के बीच तनाव के बाद व्यापार बंद हो गया है। इससे अफगान जनता को पाकिस्तान से दवाएं नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान दवाएं देने के नाम पर तालिबान सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था। भारत के ऐक्शन में आने से पाकिस्तान पर से अफगानिस्तान की निर्भरता कम हो गई है। पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद नवंबर 2025 में अफगान सरकार ने पाकिस्तान से दवाओं का आयात पूरी तरह से बैन कर दिया है। तालिबानी सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के दवाओं की गुणवत्ता बहुत खराब है। अफगान व्यापारियों को 3 महीने का वक्त दिया गया है ताकि वे पाकिस्तान से अपना आयात बंद कर दें। अफगानिस्तान अब दवाओं के लिए भारत और मध्य एशिया के देशों के साथ डील कर रहा है।

जुल्फीकार, बेनजीर को मारने वाली पाकिस्तान सेना के तलवे चाटते दिखे बिलावल भुट्टो, भारत के खिलाफ उगला जहर



इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सेना ने देश के दो प्रधानमंत्रियों को मरवाया। सबसे पहले जुल्फीकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकया और फिर बेनजीर भुट्टो की हत्या में भी

पाकिस्तान की सेना और ISI पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो, जो बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं और जुल्फीकार अली भुट्टो के नाती हैं, वो सार्वजनिक सभा में भारत का नाम लेकर उसी सेना के तलवे चाटते नजर आए। बिलावल भुट्टो ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 'पाकिस्तान की सेना ने मई महीने के संघर्ष में भारत को हरा दिया।' न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन और फ्रांस-24 के लिए लिखने वाले जर्नलिस्ट ताहा सिद्दीकी ने बिलावल भुट्टो के बयान को 'शर्मनाक' कहा है।

ताहा सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि "बिलावल भुट्टो पर शर्म आती है कि उन्होंने अपनी माँ बेनजीर भुट्टो की पुण्यतिथि का इस्तेमाल GHQ (पाकिस्तान सेना का हेडक्वार्टर) के भारत विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए किया। क्या यह पाकिस्तान आर्मी के सामने अपनी साख चमकाने (बूट पॉलिश) के लिए है, जिसने असल में उनकी मां

को मारा था? कितनी शर्म की बात है!!!"

बिलावल भुट्टो ने की पाकिस्तान सेना की बूट पॉलिश! बिलावल भुट्टो ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि "पाकिस्तान को जो जीत हासिल हो चुकी है, उसे अभी तक भारत हजम नहीं कर पा रहा है। हमारे फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी चुप हो जाते हैं।" उन्होंने इमरान खान और उनकी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि "ये जो सेना को गाली दी जाती है, ये सियासत के दायरे में नहीं होते हैं। सोचिए कैसा होता अगर जब मुझे NAB का नोटिस मिलता था, आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया जाता था, तो मैं आपने कहता कि कोर कमांडर के घर पर हमला करें। हमारे डिफेंस बेस पर हमला करें तो क्या आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती या नहीं। जुल्फीकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन हमने सियासी विरोध किया और इसीलिए बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनीं।"

आपको बता दें कि जिस पाकिस्तानी सेना के कसीदे बिलावल पढ़ रहे हैं, उसी पर उनकी मां के हत्या के आरोप हैं। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की 27 दिसंबर 2007 को हत्या कर दी गई थी। जिसमें पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा प्रतिष्ठान की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान वापसी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सीधे सेना और इंटर-सर्विसेज़ इंटेलिजेंस (ISI) के नियंत्रण में थी, इसके बावजूद उनकी सुरक्षा में गंभीर चूक सामने आई। हत्या के तुरंत बाद घटनास्थल को धो दिए गये, ताकि सबूत मिटा दिए जाएं। जिस पर सेना और तत्कालीन सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की तीखी आलोचना हुई। संयुक्त राष्ट्र की जांच रिपोर्ट (2010) ने भी निष्कर्ष निकाला कि पाकिस्तानी राज्य, विशेष रूप से सुरक्षा एजेंसियां, बेनजीर को पर्याप्त सुरक्षा देने में नाकाम रहीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जांच को जानबूझकर बाधित किया गया।

Top News इस्लाम के नाम पर भारत के पड़ोसियों को फांस रहा तुर्की,

इस्लाम के नाम पर भारत के पड़ोसियों को फांस रहा तुर्की, खलीफा का दक्षिण एशिया में नापाक 'ऑटोमन' प्लान

अंकारा: भौगोलिक तौर पर तुर्की दक्षिण एशिया से बहुत दूर है, लेकिन इस्लाम के धागे से वो भारत के पड़ोसी देशों को एक गाँठ में बांध रहा है। इतिहास में तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के इस क्षेत्र पर काफी प्रभाव रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन फिर से 500 साल पुराने उस इतिहास को दोहराना चाहते हैं। तुर्की दक्षिण एशिया के मुस्लिम देशों के साथ करीबी संबंध बनाकर इस क्षेत्र की भूराजनीति को प्रभावित करना चाहता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि 10 नवंबर को लाल किले पर हुए बम धमाके में तुर्की की इस विचारधारा का और उसके एक हैडलर की भूमिका थी। वहीं, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान, तीन भाई की तरह भारत के खिलाफ एक साथ आ गये हैं।

भारत लंबे समय से रोमन साम्राज्य के साथ सीधे व्यापार करता था, जिसमें पूर्वी रोमन (बीजान्टिन) साम्राज्य भी शामिल था, जिसका मुख्यालय कॉन्स्टेंटिनोपल, यानि आधुनिक इस्तांबुल में था। हालांकि, मध्य पूर्व और मिस्र के बड़े हिस्से पर अरबों की जीत के बाद भारत और बीजान्टिन के बीच सीधे संबंध और व्यापार कम हो गया। तुर्की के आक्रांताओं ने भारत पर हमले भी किए।

दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे कई प्रमुख भारतीय मुस्लिम राज्य, तुर्की राजवंशों और सेनाओं ने स्थापित किए थे।

तुर्की कैसे दक्षिण एशिया से फिर संबंध जोड़ रहा? 16वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने न सिर्फ भारतीय समुद्री व्यापार में दिलचस्पी ली, बल्कि पुर्तगालियों और सफवी ईरान के खिलाफ क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए भारतीय शक्तियों से गठजोड़ भी किया। तुर्की ने ही बाबर को तोपें और बारूद दी थी, ताकि वो मुगल साम्राज्य की नींव रख सके। मुगल सत्ता ढहने और ब्रिटिश शासन के दौरान भी ओटोमन खलीफा भारतीय मुसलमानों के लिए काफी मायने रखे ते। खिलाफत आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसमें भारतीय मुसलमानों ने ओटोमन खिलाफत को बचाने के लिए इस्लामिक आंदोलन कर दिया था। हैदराबाद रियासत तक ने खिलाफत को फिर से जिंदा करने के लिए योजनाएं बनाई थी। हैदराबाद के निजाम के बेटों, आसफ जाह राजवंश के वंशजों की शादी ओटोमन राजकुमारियों से हुई थी। हालांकि ओटोमन की फिर से स्थापना की सारी कोशिशें नाकाम हुईं, लेकिन ये घटनाएं ये साबित करती हैं कि

दक्षिण एशिया में तुर्की का प्रभाव सिर्फ भूराजनीतिक नहीं, बल्कि इस्लाम के नाम पर है, जिसमें भावनात्मक उबाल आता रहता है।

तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन फिर से दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इसके लिए इस्लाम से बढ़कर और कोई भावनात्मक रस्सी नहीं है। पाकिस्तान को मई महीने में भारत के खिलाफ हथियार देकर तुर्की ने इसी की आजमाइश की थी। अब वो बांग्लादेश और मालदीव को भी इसी धागे से बांध रहा है। चूंकी ये देश इस्लामिक हैं और भारत विरोधी रूख रखते हैं, तो तुर्की इन्हें एक मसीहा की तरह लगता है। तुर्की भारत की शक्ति को संतुलित करने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और अजरबैजान देशों के साथ मजबूत रिश्ते बना चुका है। इसका एक मकसद भारत के बाद ईरान को भी संतुलित करना है, जो एक शिया देश है और जिसका प्रभाव खाड़ी देशों में तुर्की से कम नहीं है।

एर्दोगन के दक्षिण एशिया नीति से भारत पर क्या असर? द डिप्लोमेट में जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट

अखिलेश पिल्ललमरी ने लिखा है कि राष्ट्रपति एर्दोगन, ओटोमन और मुगल दोनों साम्राज्यों के पतन को ऐसी त्रासदी मानते हैं जिन्हें ठीक किया जाना चाहिए। इस तरह की सोच ने पाकिस्तान के साथ तुर्की के संबंधों को मजबूत किया है। अखिलेश पिल्ललमरी के मुताबिक इसलिए, दक्षिण एशिया में तुर्की की नई दिलचस्पी दो मजबूरियों से पैदा होती है। पहला, उपमहाद्वीप की बड़ी मुस्लिम आबादी और उसके मुस्लिम देशों के साथ तुर्की के संबंध मुस्लिम दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा और भूमिका को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, तुर्की की संस्कृति पाकिस्तान में तेजी से लोकप्रिय हो रही है और कई पाकिस्तानी, तुर्की को एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं और फॉलो करते हैं।

दूसरा, दक्षिण एशिया के मुस्लिम देश, खासकर पाकिस्तान के साथ सुरक्षा और राजनयिक संबंध, तुर्की के भू-राजनीतिक हितों को पूरा करता है। ये संबंध तुर्की को अपने हथियारों की क्षमता दिखाने, क्षेत्र में अरब दुनिया के प्रभाव के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने, पूरे मध्य और दक्षिण एशिया में शक्ति दिखाने और अपने चिर प्रतिद्वंद्वी ईरान को रोकने में सक्षम बनाते हैं।



महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ



नंदिग्राम टाईम्स

Tuesday 30th December 2025 वर्ष - 9 , अंक 244 , पृष्ठ 03

छत्रपति संभाजीनगर महापालिका चुनाव: महायुती में दरार, शिंदेसेना ने भाजपा के प्रस्ताव ठुकराए, भाजपा ने आत्मनिर्भर होकर अकेले लड़ने का संकेत

छत्रपति संभाजीनगर, 29 दिसंबर 2025: आगामी छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका चुनावों को लेकर महायुति गठबंधन में गंभीर दरार उभरने लगी है। भाजपा और शिंदेसेना के बीच सीट-वाटप को लेकर चल रही बैठकों में सहमति न बनने पर स्थानीय तनाव visibly बढ़ गया है। शिंदेसेना के पालकमंत्री संजय शिरसाट ने भाजपा द्वारा पेश किए गए चार प्रस्तावों को खारिज कर दिया, जिससे गठबंधन वार्ता ठप्प हो गई है और भाजपा ने अब अकेले चुनाव लड़ने का स्पष्ट संकेत दिया है।

भाजपा नेता और ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे ने कहा है कि भाजपा अब शाम तक आखिरी बार शिंदेसेना को संशोधित प्रस्ताव देगी, लेकिन अगर वह स्वीकार नहीं किया गया तो पार्टी “स्वबळ”, यानी अकेले चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। उनके बयान से महापालिका चुनावों में युति की संभावना कम दिखाई दे रही है और गठबंधन के टूटने का संकेत भी मिल रहा है।

भाजपा और शिंदेसेना के बीच सीट-बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद ने स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस पैदा कर दिया है। शिंदेसेना की मांग है कि उसे बड़ी

संख्या में सीटें मिलनी चाहिए, जबकि भाजपा शून्य से अधिक हिस्सेदारी चाहता है, जिससे बातचीत गतिरोध में फँसी हुई है।

आज सुबह भाजपा के स्थानीय नगराध्यक्ष किशोर शितोळे, विधायक संजय केणेकर तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शिरसाट के बंगले का दौरा किया और बैठक का दबाव बढ़ाया, पर शिंदेसेना ने अपने रुख में क्रायम रहते हुए कोई समझौता नहीं किया।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महायुति के शीर्ष नेतृत्व द्वारा गठबंधन को बनाए रखने के निर्देश देने के बावजूद स्थानीय स्तर पर सीट-वाटप को लेकर मतभेद गंभीर रूप से सामने आए हैं। यह संघर्ष छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका में भाजपा-शिंदेसेना के भविष्य के सहयोग पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।

चुनावों में कौन सा समीकरण अंतिम रूप से सामने आएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, पर इस गतिरोध से यह संकेत मिलता है कि संभाजीनगर में चुनावी रणभूमि और भी अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होगी। मतदाता अब यह तय करेंगे कि महायुति गठबंधन एकजुट होकर आगे बढ़ेगी या भाजपा स्वतंत्र रूप से चुनाव का सामना करेगी।

Maharashtra Politics | **महाराष्ट्र में चुनाव से पहले दो बड़े राजनीतिक परिवारों का पुनर्मिलन:**

महाराष्ट्र में चुनाव से पहले दो बड़े राजनीतिक परिवारों का पुनर्मिलन: ठाकरे और पवार की सियासी रणनीति

मुंबई | चुनावी गतिविधियों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में दो प्रमुख राजनीतिक परिवारों — ठाकरे और पवार — के बीच पुनर्मिलन का सिलसिला सुर्खियों में है। भावनात्मक कारणों से अधिक सियासी मजबूरियों के चलते यह एकजुटता देखने को मिल रही है, जो आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में बढ़त हासिल करने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

ठाकरे परिवार की बात करें तो उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के बीच करीब 20 साल की दरार रही है। दोनों नेताओं ने शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के बीच गठबंधन करके पुनः एक साथ चुनावी मंच साझा किया। हालांकि 2025 के बेस्ट एम्प्लॉयीज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी चुनाव में उनका यह गठबंधन उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाया और 21 सीटों में से एक भी जीत नहीं सका। इस परिणाम ने स्पष्ट कर दिया कि केवल एकता ही काफी नहीं है, उसे जमीनी समर्थन की भी आवश्यकता है।



अब उनकी नज़र 2026 में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों पर है, जिनमें मुंबई, ठाणे और कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उन्हें बेहतर प्रदर्शन हासिल करने की जरूरत है।

दूसरी ओर, पवार परिवार में भी गत वर्षों में मतभेद देखने को मिले थे। शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच



राजनीतिक मतभेदों ने 2023 में पार्टी विभाजन तक पहुंचा दिया था। तब अजित पवार ने भाजपा-शिवसेना शिवसेना (UBT) के साथ गठबंधन किया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में कमजोर प्रदर्शन और सियासी वास्तविकताओं ने यह संकेत दिया कि अलग राहें अपना राणनीतिक रूप से सफल नहीं रहा।

परिणामस्वरूप, दोनों पक्ष अब 15 जनवरी को होने वाले पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव के लिए एक साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। यह कदम पवार परिवार की राजनीतिक जड़ें मजबूत करने और संगठनात्मक आधार को पुनः जागृत करने की कोशिश है।

विश्लेषकों के अनुसार, दोनों परिवारों की यह वापसी व्यक्तिगत रिश्तों की पुनर्स्थापना से ज्यादा चुनावी गणित और राजनीतिक अस्तित्व की बहाली से प्रेरित है। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में इन संयुक्त ताकतों के प्रदर्शन से महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसे में यह पुनर्मिलन भावनाओं से अधिक रणनीतिक सियासी कदम के रूप में देखा जा रहा है।

नागपुर के कॉलेज हॉस्टल में 20 दिनों से जूनियर्स की रैगिंग, गुमनाम लेटर ने खोला राज, निकाली गई 19 छात्राएं

20 दिनों से जूनियर्स की रैगिंग



नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सरकारी आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल के 19 छात्राओं को रैगिंग के आरोप में तीन महीने के लिए कॉलेज के हॉस्टल से निकाल दिया गया है। ये सभी छात्राएं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हैं। यह फैसला कॉलेज प्रशासन ने एंटी-रैगिंग कमेटी की जांच के बाद लिया है।

एंटी-रैगिंग कमेटी ने की जांच कॉलेज प्रशासन की एंटी-रैगिंग कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि ये सभी छात्राएं रैगिंग में शामिल थीं। छात्राओं को क्लास अटेंड करने की परमीशन फिलहाल के लिए दी गई है। कॉलेज ने सभी छात्राओं से लिखित में चेतावनी ली है कि अगर वह दोबारा रैगिंग में शामिल पाई जाती हैं तो उन्हें 6 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड या फिर स्थायी रूप से कॉलेज से निष्कासित किया जा

कॉलेज ने छात्राओं को हॉस्टल से निकाला कॉलेज प्रशासन ने एक गुमनाम शिकायत के बाद यह पूरी कार्रवाई की है। प्रशासन को शिकायत में कहा गया था कि कॉलेज के प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स को 20 दिनों से लगातार परेशान किया जा रहा था। शिकायत में लिखा था कि सभी स्टूडेंट्स डर के माहौल में कॉलेज में रह रहे हैं। शिकायत में आगे लिखा था कि कॉलेज में रात भर रैगिंग चलती है और हॉस्टल का स्टाफ इन घटनाओं की तरफ ध्यान नहीं देता है। इस पूरी शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन ने 18 दिसंबर को जांच शुरू की और स्टूडेंट्स के बयान दर्ज किए। जांच के बाद कॉलेज की एंटी-रैगिंग कमेटी ने 19 छात्राओं को रैगिंग में शामिल पाया और उन्हें तीन महीने के लिए हॉस्टल से निकाल दिया।



मुंबई भांडुप पश्चिम में BEST बस हादसा: 4 की मौत, 9 घायल

मुंबई : भांडुप (वेस्ट) के स्टेशन रोड पर सोमवार रात करीब 10 बजे बीईएसटी (BEST) की एक बस के रिवर्स लेते समय पैदल चल रहे लोगों के बीच में जा टकराने से कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड, BEST स्टाफ और 108 एम्बुलेंस तैनात कराकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बस भीड़ वाले इलाके में रिवर्स करते समय पैदल

यात्रियों को कुचलते हुए आगे बढ़ी, जिससे अफरा-तफरी मच गई। शुरुआती जांच में यह संकेत मिल रहा है कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही या तकनीकी कारणों से हुआ हो सकता है, हालांकि सटीक वजहों का पता पुलिस जांच के बाद ही चलेगा।

पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारण इलाके में ट्रैफिक प्रभावित रहा और स्थानीय नागरिक हादसे की भयावहता से परेशान दिखे। अधिकारी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं।

बीएमसी चुनाव 2026: महायुति में सीट शेयरिंग तय, भाजपा 137 और शिवसेना 90 सीटों पर लड़ेगी



मुंबई, 30 दिसंबर 2025: आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे का फ़ॉर्मूला फाइनल हो गया है। इसके अनुसार भाजपा 227 सीटों में से 137 सीटों पर अपने चुनावी प्रत्याशी उतारेगी, जबकि शिवसेना 90 सीटों पर चुनावी मैदान में होगी।

यह सीट-शेयरिंग मुंबई महापालिका चुनावों को लेकर चल रही लंबी वार्ताओं का नतीजा है, जिसमें दोनों पक्षों ने उम्मीदवारों की सूची और प्रचार रणनीतियों पर सहमति बनाई है। भाजपा अध्यक्ष अमित साठम ने कहा है कि इस समझौते के तहत महायुति गठबंधन संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगा और एकजुट प्रयास करेंगे।

नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है और इसके बाद प्रत्याशी अपना नामांकन फाइनल करेंगे। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी 2026 को आयोजित होंगे, जबकि मतगणना 16 जनवरी को होगी।

Maharashtra Politics | **अजित पवार के ऐलान से सियासी भूकंप**

परिवार साथ आ रहा, अजित पवार के ऐलान से सियासी भूकंप, संजय राउत ने 'चाचा-भतीजे' के साथ अमित शाह को घेरा

मुंबई | महाराष्ट्र में मुंबई बीएमसी समेत 29 नगर महापालिकाओं के लिए मंगलवार तक नामांकन किए जा सकेंगे। ठाकरे ब्रदर्स के बाद अब महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार ने ऐलान किया है कि परिवार एक साथ आ रहा है। अजित पवार की एनसीपी ने शरद गुट वाली एनसीपी के साथ पिंपरी चिंचवड में गठबंधन का ऐलान किया है। पिंपरी चिंचवड नगर निगम पर बीजेपी ने पिछली बार जीत दर्ज की थी। ऐसे में यहां पर मुकाबला एनसीपी (शरद-अजित) बनाम बीजेपी होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में नए घटनाक्रम पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने निशाना साधा है। राउत ने कहा है कि अजित पवार को बीजेपी को जवाब देना होगा कि बीजेपी जिस शरद पवार से लड़ रही है। वह उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। राउत ने आगे कहा कि जवाब अभित शाह और शरद पवार को देना होगा। उनसे पूछिए।



अजित पवार ने क्या कुछ कहा? बारामती में उद्योगपति गौतम अडानी की मौजूदगी में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ मंच साझा किया था। इस कार्यक्रम के बाद रविवार शाम को अजित पवार ने ऐलान किया था कि परिवार एक साथ आ रहा है। अजित पवार ने PCMC (पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन) चुनावों के लिए शरद पवार गुट के साथ गठबंधन की घोषणा की थी। उन्होंने संकेत दिए थे कि जल्द ही सीट-बंटवारे पर समझौता होगा। एनसीपी के दो फाड़ होने और

महाराष्ट्र के हित में लेंगे बड़े फैसले अजित पवार ने कहा था कि एक परिवार एक साथ आ रहा है क्योंकि बहुत से लोग ऐसा चाहते थे। उन्होंने कहा था कि हम एक किसान परिवार से आते हैं। खेती हमारी जाति है। महाराष्ट्र के बड़े हित में कुछ फैसले लेने होंगे। यह दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की पहली आधिकारिक घोषणा है, जबकि पुणे सहित अन्य नगर निगमों में गठबंधन के लिए बातचीत जारी है। रैली के दौरान, पवार ने वार्ड 12 के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की, जहां अविभाजित एनसीपी ने 2017 के चुनावों में सभी चार सीटें जीती थीं। उम्मीदवार पंकज भालेकर, शरद भालेकर, सीमा भालेकर और चारुलता सोनवणे हैं। गौरतलब हो कि अजीत पवार के नेतृत्व में पहले 1992 और 1999 के बीच कांग्रेस और फिर अविभाजित एनसीपी ने 1999 और 2017 के बीच पिंपरी चिंचवड पर शासन किया। बीजेपी ने 2017 में 128 सीटों में से 77 सीटें जीतकर नगर निकाय पर नियंत्रण कर लिया, जबकि एनसीपी दूसरे स्थान पर रही।

मालेगांव महापालिका चुनाव: एमआईएम से गठबंधन संभव तो ठीक, नहीं तो कांग्रेस अकेले मैदान में; 9 प्रत्याशियों की घोषणा

मालेगांव: आगामी मालेगांव महानगरपालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि यदि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के साथ गठबंधन संभव हुआ तो उसी के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, अन्यथा कांग्रेस अपने दम पर (स्वबळ) चुनावी मैदान में उतरेगी। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने अपने पहले चरण में 9 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ समय से कांग्रेस और एमआईएम के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही थी। मालेगांव की स्थानीय राजनीति में दोनों दलों के बीच तालमेल की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन प्रदेश स्तर पर कांग्रेस नेतृत्व की ओर से एमआईएम व मनसे जैसी पार्टियों के साथ सीधे गठबंधन को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद यह प्रयास कमजोर पड़ गया। परिणामस्वरूप कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि आगे चलकर महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के साथ सीटों को लेकर सहमति बनती है, तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन एनसीपी दूसरे स्थान पर रही।

फिलहाल पार्टी ने अपनी स्वतंत्र चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पूर्वी मालेगांव के कुछ वार्डों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं।

घोषित प्रत्याशियों में प्रभाग 2 से महमंद यासीन शकील अहमद, प्रभाग 3 से आफरीन परवीन शेख, प्रभाग 7 से रशिदा अय्युब अब्दुल कयुम, प्रभाग 17 से अशरफ अली नबी सरवर, प्रभाग 18 से एजाज बेग, रियाज बेग व यास्मीन बेग, प्रभाग 20 से अब्दुल अहात कलीमउद्दीन तथा प्रभाग 21 से तस्लीमा जैनु पठाण के नाम शामिल हैं।

इन नामों की घोषणा के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ वार्डों में एक ही परिवार से उम्मीदवार दिए जाने को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह केवल पहली सूची है और आने वाले दिनों में पश्चिमी मालेगांव के प्रत्याशियों की घोषणा भी की जाएगी।

एमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर अनिश्चितता और कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के संकेतों ने मालेगांव की चुनावी राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है। जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे राजनीतिक समीकरण और भी स्पष्ट होते नजर आ रहे हैं।



परभणी: चार महापौर हो गए, फिर भी मूलभूत समस्याएँ बरकरार



परभणी, 29 दिसंबर 2025: परभणी महानगरपालिका बनने के 13 साल बाद भी शहर की मूलभूत समस्याएँ जस की तस बनी हुई हैं। अब तक चार महापौरों के कार्यकाल गुजरने के बावजूद नागरिकों को नियमित पानी चार-पाँच दिन में एक बार ही मिलता है, और पानी की दीर्घकालीन योजना आज तक लागू नहीं हुई है। वहीं शहर की सड़कों की स्थिति चिंताजनक है, कई सड़कें अथूरी या खराब हालत में हैं, जिससे रोज़मर्रा की यातायात समस्या बनी हुई है। पार्किंग और कचरा प्रबंधन भी संतोषजनक नहीं है, कई इलाकों में कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं।

महापालिका के वास्तविक विकास और योजनाओं की पूर्णता के बावजूद, अथूरे पड़े पायाभूत विकास कार्य तथा प्रशासनिक विलंब पर नागरिकों में निराशा है। जनता नए प्रशासन से बदलाव की उच्च उम्मीदें व्यक्त कर रही है कि जल्द ही पानी, सफाई और सड़कों जैसे मूलभूत मुद्दों का स्थायी समाधान मिलेगा।

शासन के पास लंबित पेंशनर्स की मांगें पूरी कराई जाएंगी : विधायक कल्याणकर



नांदेड़ | संवाददाता : शासन के पास वर्षों से लंबित पेंशनधारकों की विभिन्न मांगों को विधानसभा में मजबूती से उठाकर उन्हें हल कराने का आश्वासन विधायक बालाजीराव कल्याणकर ने दिया। वे विजयनगर स्थित हनुमान मंदिर

मंगल कार्यालय में आयोजित पेंशनर्स डे कार्यक्रम में बोल रहे थे।

इस अवसर पर मंच पर पेंशनर्स संघ के अध्यक्ष डी. एम. रेड्डी, सचिव चंद्रकांत जटाळ, उपाध्यक्ष एम. मीराखान, वरिष्ठ साहित्यकार जगदीश कदम, जिला कोषागार अधिकारी विक्रम देशमुख, लेखाधिकारी नीलकंठ पांजगे, नामदेवराव राठोड, अपर कोषागार अधिकारी संजय येर्रे, गज़लकार बापू दासरी, पत्रकार डॉ. अभयकुमार दांडगे, जे. पी. मिसाळे सहित अनेक मान्यवर उपस्थित थे।

कार्यक्रम की शुरुआत संघ के सचिव चंद्रकांत जटाळ ने की। विधायक बालाजीराव कल्याणकर का स्वागत अध्यक्ष डी. एम. रेड्डी ने शाल व पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। अन्य सभी अतिथियों का भी शाल एवं पुष्पगुच्छ से सम्मान किया गया। कार्यक्रम का प्रस्तावना उपाध्यक्ष एम. मीराखान ने रखी। इसके पश्चात पेंशनर्स की विभिन्न

मांगों का ज्ञापन विधायक को सौंपा गया। इस कार्यक्रम में लगभग 550 पेंशनधारक सदस्य उपस्थित रहे। 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 78 वरिष्ठ पेंशनधारकों का विधायक एवं अतिथियों के हाथों शाल व पुष्पगुच्छ देकर विशेष सम्मान किया गया। मनोगत व्यक्त करते हुए जिला कोषागार अधिकारी विक्रम देशमुख ने आश्चस्त किया कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। लेखाधिकारी नीलकंठ पांजगे ने पेंशनधारकों की तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं पर विस्तार से जानकारी दी। वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. जगदीश कदम ने ज्येष्ठ पेंशनर्स को प्रेरणादायी मार्गदर्शन किया।

अध्यक्षीय समारोप में डी. एम. रेड्डी ने संगठन को 41 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन बापू दासरी ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन एस. एस. कुरुडे ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में इंजि. डी. एम. रेड्डी सहित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने विशेष परिश्रम किए।

नांदेड़ महापालिका चुनाव: भाजपा 'एकला चलो रे' रणनीति के साथ अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस-उद्धवसेना गठबंधन में मैदान में उतरेगी



नांदेड़ : नांदेड़ महानगरपालिका के आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 'एकला चलो रे' की रणनीति अपनाते हुए अकेले मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। भाजपा-शिंदे सेना के बीच युति की चर्चा लंबे समय से चल रही थी, लेकिन सीटों के बंटवारे पर दोनों दलों के बीच असहमति बनी रहने से इस बैठक का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने विपक्षी दलों से गठबंधन न कर स्वयं ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे स्पष्ट रूप से उसकी रणनीति अलग राह पर जाने की है।

भाजपा और शिंदेसेना के बीच चल रही बातचीत में प्रमुख मुद्दा सीटों का बंटवारा रहा। शिंदेसेना ने दक्षिण और उत्तर नांदेड़ से क्रमशः अधिक सीटें मांगी थीं, लेकिन भाजपा सिर्फ 8 सीटों के ऊपर देने को तैयार नहीं हुई, जिससे गठबंधन टूट गया। इस पर भाजपा नेतृत्व ने 'एकला चलो रे' का नारा अपनाकर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने

का निर्णय लिया।

दूसरी ओर, भाजपा की रणनीति को चुनौती देने के लिए कांग्रेस और उद्धवसेना (शिवसेना UBT) ने मिलकर महाविकास आघाडी के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। महापालिका की 81 सीटों में से लगभग 20 सीटों पर उद्धवसेना अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि शेष पर कांग्रेस उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की योजना बन रही है। स्थानीय नेताओं का दावा है कि यह गठबंधन भाजपा को कड़ी टक्कर देगा।

इस गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस सांसद रवींद्र चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष राजेश पावडे और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई है। आघाडी ने चुनावी रणनीति तय करने के लिए सभी संभावित सहयोगियों से बातचीत तेज कर दी है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भाजपा की अकेली रणनीति और कांग्रेस-उद्धवसेना का गठबंधन नांदेड़ महापालिका चुनाव को और अधिक रोचक और प्रतिस्पर्धात्मक बना देगा। मतदाता अब यह तय करेंगे कि क्या भाजपा की स्वतंत्र लाठी-मार रणनीति सफल होती है या महाविकास आघाडी की संयुक्त ताकत आगे बढ़ती है। परिणाम अगले कुछ हफ्तों में स्पष्ट होंगे।

मुंबई : मुंबई में साइबर ठगों ने एक 68 वर्षीय वृद्ध महिला को 'डिजिटल अरेस्ट' के बहाने लगभग ₹3.71 करोड़ की ठगी की है। आरोपियों ने खुद को सीबीआई, पुलिस और पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ के रूप में पेश कर महिला को डराया-धमकाया कि उसके खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने एक नकली वर्चुअल कोर्ट सत्र का आयोजन किया, जहाँ "जस्टिस चंद्रचूड़" के नाम से धोखेबाज़ ने महिला से उसकी सभी जमा-पूंजी "जांच" के लिए ट्रांसफर करने को कहा।

महिला डर के कारण महीनों (अगस्त से अक्टूबर 2025 तक) में कई बैंक खातों में कुल ₹3.71 करोड़ जमा कर बैठी, जब उसके बाद आरोपियों ने संपर्क बंद कर दिया,



हिमायतनगर नगरपंचायत के नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष शेख रफिक शेठ का सोनारी में शेख खयूम (पत्रकार) और परिवार द्वारा भव्य सत्कार किया गया।

नांदेड़ महापालिका चुनाव: टिकट चाहे किसी भी पार्टी का हो, उम्मीदवार तैयार हैं मैदान में उतरने को



कई उम्मीदवार मानते हैं कि टिकट किसी भी पार्टी का हो, यह केवल माध्यम है। उनका कहना है कि विधानसभा या महापालिका में सदस्य बनने का उद्देश्य अपने प्रभाग के व्यापक विकास को प्राथमिकता देना होना चाहिए। वे अपने क्षेत्र के मतदाताओं से सीधे संपर्क स्थापित करने और स्थानीय मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता साबित करने में जुटे हुए हैं।

यह भी देखा गया है कि कुछ उम्मीदवार ने एक ही समय में कई दलों से नामांकन दाखिल किया है। उदाहरण के लिए, एक महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस, वंचित बहुजन आघाड़ी और अपक्ष के रूप में तीन अलग-अलग फॉर्म जमा किए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अंत में तो वह उम्मीदवार ही मुख्य बनेगा, जिसके पास संबंधित पार्टी का अधिकृत एबी फॉर्म होगा।

चुनाव प्रचार और रसद को लेकर भी प्रत्याशी सक्रिय हैं। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मिलकर मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर काम तेज़ी से चल रहा है। 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को परिणाम घोषित होने की घोषणा पहले ही हो चुकी है, और इसके पहले सभी उम्मीदवार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि टिकट वितरण पर असमंजस और इच्छुक उम्मीदवारों की सक्रियता इस चुनाव को और भी प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगी। अंतिम उम्मीदवारों की सूची जैसे-जैसे स्पष्ट होगी, चुनावी समीकरण और स्पष्ट रूप से सामने आएंगे।

मुंबई में 'डिजिटल अरेस्ट' साइबर फ्रॉड: नकली जज बनकर 3.71 करोड़ की ठगी, एक गिरफ्तार



तब उसे धोखाधड़ी का अहसास हुआ और उसने साइबर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की।

जांच के दौरान पता चला कि रकम को कई "मूल" खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था, जिनमें से एक का पता सूरत (गुजरात) में चला। वहां से एक 46 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसने फर्जी कंपनी का बैंक खाता खोलकर ठगों के

लिए पैसे प्राप्त किए। पुलिस का कहना है कि वह लगभग ₹1.71 करोड़ अपने खाते से फ्रॉड करने वालों को ट्रांसफर करने में शामिल था और उसे कमीशन भी मिला था।

पुलिस अन्य मुख्य सरगनाओं और गिरोह के सदस्य की तलाश कर रही है, जिनके विदेश में होने का संदेह है। यह घटना साइबर अपराध के बढ़ते खतरों और डिजिटल धोखाधड़ी से सावधान रहने की आवश्यकता को उजागर करती है।